आगरा–लखनऊ ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेस–वे का रूट तय

पीपीपी अनुश्रवण समिति ने कॉन्सेप्ट रिपोर्ट की समीक्षा की

लखनऊ, 27 अगस्त, 2012: आगरा से लखनऊ प्रवेश–नियंत्रित ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेस–वे के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तत्पर राज्य सरकार की **सार्वजनिक–निजी सहभागिता अनुश्रवण समिति** (पीपीएमसी) ने आज परामर्शी मे. रेडिकॉन इण्डिया प्रा लि द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट रिपोर्ट की समीक्षा की। **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में समिति ने इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के संरेखण (एलाइनमेन्ट) को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया।**

सार्वजनिक–निजी सहभागिता के आधार पर बनने वाले इस 6 लेन (8 लेन तक विस्तारित करने योग्य) एक्सप्रेस–वे के अंतिम रूट के निर्णयानुसार **यह लगभग 270 किमी लम्बा होगा तथा यमुना एक्सप्रेस–वे के पास आगरा की प्रस्तावित रिंग रोड से शुरू होकर फतेहाबाद, शिकोहाबाद, सैफई, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 के निकट इटावा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 91 के निकट कन्नौज, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25ए के निकट मलिहाबाद से होता हुआ लखनऊ की आंतरिक रिंग रोड पर खत्म होगा।** ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सप्रेस–वे पर **पाँच टोल–प्लाज़ा, आठ इन्टरचेन्ज तथा 7.5 मीटर की सर्विस लेन के साथ 80 अण्डरपास, 135 कैटल पास और चार जन–सुविधा केन्द्र प्रस्तावित हैं।**

पीपीपी अनुश्रवण समिति ने परामर्शी से कॉन्सेप्ट रिपोर्ट में **अधिकतम 120 किमी प्रति घण्टा की गति के लिए डिज़ाइन मानक सम्मिलित करने के लिए कहा है।** समिति का यह मत भी था कि **कॉनसेप्ट रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परियोजना हेतु भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी,** सरकार केवल मदद करेगी। साथ ही कॉन्सेप्ट रिपोर्ट में **वार्षिक–वृत्ति (Annuity) तथा टोल आधारित वैकल्पिक वित्तीय मॉडल,** एक्सप्रेस–वे पर **दो ईंधन/पेट्रोल पम्प** की स्थापना को भी शामिल किया जाएगा। **आगरा की आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, फिरोज़ाबाद के काँच उद्योग, कन्नौज के इत्र व कानपुर के चमड़ा उद्योग को लाभ पहुँचाने के दृष्टि से यहाँ पहले से ही स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों से भी जोड़ने का प्रावधान** किया जाएगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– *"बंजर व बेकार भूमि के अधिकतम उपयोग के आधार पर एक्सप्रेस–वे के अंतिम रूट का निर्णय किया गया है।" उन्होंने कहा कि इस परियोजना से किसानों व क्षेत्रीय नागरिकों को व्यापक लाभ पहुँचाने के लिए एक्सप्रेस–वे के किनारे जगह–जगह पर छोटी कृषि मण्डियाँ, स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र भी बनाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़क के साथ–साथ हरित पट्टी, झीलें व वर्षा जल–संचयन का प्रावधान भी किया जाएगा।*

श्री गुप्ता ने बताया कि *परामर्शी से कॉनसेप्ट रिपोर्ट में सम्पूर्ण परियोजना अथवा विकास केन्द्र से विकास केन्द्र के विभिन्न भागों के लिए विकासकर्ता के चयन का वैकल्पिक प्रावधान करने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रस्तावित एक्सप्रेस–वे के रूट में पड़ने वाले नगरों के मास्टर–प्लान और परियोजना के संरेखण में समन्वय भी स्थापित किया जाएगा जिससे क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए।*

यूपीडा के सी0ई0ओ0 श्री मुकुल सिंघल ने बताया यूपीडा एवं पीपीपी अनुश्रवण समिति की टिप्पणियाँ परामर्शी को आगामी माह की शुरूआत में उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसके बाद पीपीपी अनुश्रवण समिति अंतिम कॉन्सेप्ट रिपोर्ट को मंजूर करेगी।

इस एक्सप्रेस–वे के बन जाने से आगरा से लखनऊ की दूरी को वर्तमान में 7 घण्टे के स्थान पर 3 घण्टे में तय करने के साथ–साथ इसके रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्रों के किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बड़े बाजारों में त्वरित गति से पहुँचाया जा सकेगा तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यह एक्सप्रेस–वे पहले से ही चालू यमुना एक्सप्रेस–वे से जुड़ जाएगा।

बैठक में सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–संजय प्रसाद; विशेष सचिव, अवस्थापना विकास डॉ रोशन जैकब तथा वित्त, योजना, विधि, सिंचाई, आवास, नगर विकास आदि विभागों के उच्चाधिकरियों ने भाग लिया।